ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

16 मई, 2018 • वर्ष 1, अंक 17

सात दिन – सात पृष्ठ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 मई, 2018 को नई दिल्ली में भेंट की

- भारत और नेपाल के संबंधों का नया आयाम अयोध्या – जनकपुर बस सेवा
- हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता
- उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में निवेश करेंगी अमेरिकी कम्पनियां
- 28.63 लाख किसान जुड़े एम-किसान पोर्टल से
- वाराणसी पहुंचकर सीएम ने लिया स्थिति का जायजा

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

भारत और नेपाल के संबंधों का नया आयाम
अयोध्या – जनकपुर बस सेवा

तीर्थयात्रियों को सुविधा

भारत और नेपाल दोनों देश हजारों सालों से सांस्कृतिक व सामाजिक सबन्धों से जुड़े हुये हैं। भारत से लाखों लोग पशुपति नाथ के दर्शन के लिए नेपाल जाते हैं। इसी प्रकार लाखों लोग नेपाल से भारत आते हैं। महाराज दशरथ और राजा जनक का अटूट सम्बन्ध था। अयोध्या का जनकपुर और काठमांडू का काशी के साथ अटूट सम्बन्ध है। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है तो जनकपुर माता सीता की। इस प्रकार दोनों तीर्थ परस्पर संबंधी हैं और इन्हीं संबंधों को नया आयाम मिला है अयोध्या और जनकपुर के मध्य बस सेवा के रूप में।

अयोध्या–जनकपुर धाम बस सेवा दोनों राष्ट्रों के संबंधों को और मजबूत करेगी। इस बस सेवा के माध्यम से विकास की नई यात्रा भी आरंभ होगी।

भारत सरकार ने राम–जानकी मार्ग को पूर्ण करने का महान उत्तरदायित्व लिया है। मार्ग बन जाने के उपरान्त जनकपुर से अयोध्या पहुंचने में 10 से 12 घंटे की जगह मात्र 6 से 7 घंटे ही लगेंगे।

अयोध्या से जनकपुर के मध्य बस सेवा के जरिए श्रद्धालु भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या धाम तथा माता जानकी की जन्मस्थली जनकपुर धाम के बीच की 520 किलोमीटर की दूरी को सरलता और सुविधापूर्ण ढंग से तय कर सकेंगे।

राज्य सरकार ने सरयू आरती की भव्य शुरुआत की है तथा रामलीला का अनवरत मंचन भी प्रारम्भ कराया है। अयोध्या के समुचित विकास हेतु सरयू जी में गिर रहे नालों को बन्द किया जायेगा। अयोध्या की ख्याति के अनुसार घाटों का विस्तार किया जाएगा।

सांस्कृतिक एकता को मजबूती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती देने का कार्य रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने नेपाल के जनकपुर से इस ऐतिहासिक बस सेवा का शुभारंभ किया और अयोध्या पहुचने पर अतिथियों की अगवानी करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बस यात्रा के प्रारम्भ होने से भारत और नेपाल के बीच रामायण कालीन सम्बन्धों का नवीनीकरण हो रहा है, इससे धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा। यह बस सेवा पड़ोसी देश के पौराणिक काल से चले आ रहे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगी।

अयोध्या के विकास के लिए 133 करोड़ रुपए के कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं, जिनका हर 15 दिन पर निरीक्षण किया जा रहा है। अगले वर्ष दीपोत्सव तक अयोध्या में कराये जा रहे विकास कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। ▪

वाराणसी पहुंचकर सीएम ने लिया स्थिति का जायजा

मृतकों और घायलों के परिवारीजनों के लिए क्रमश: 5 लाख और 2 लाख की आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने दिए हादसे की जांच के आदेश, 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वाराणसी में कैण्ट स्टेशन के सामने निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिरने की दुर्घटना पर दु:ख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों को बचाव एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिये। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एन.डी.आर.एफ. को भी लाया गया।

समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस हादसे में घायल लोगों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था तथा हर सम्भव मदद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी 48 घण्टे में अपनी रिपोर्ट देगी और दुर्घटना के दोषियों का पता लगाया जा सकेगा।

4 अफसर हुए निलम्बित

हादसे के लिए प्रारंभिक रूप से दोषी पाये गये सेतु निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सहायक अभयन्ता, तथा अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

शीघ्र शुरू होगा ग्राम स्वराज का दूसरा चरण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गोरखपुर भ्रमण के दौरान कहा कि ग्राम स्वराज अभियान का दूसरा चरण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। पहले चरण में चयनित गांवों को 21 मई तक सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संतृप्त कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

पांच व्यक्तियों को दें योजनाओं का लाभ

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा रात्रि चौपाल के माध्यम से जनप्रतिनिधि जनसमुदाय से जुड़ सकेंगे और उनके दु:ख दर्द में शामिल होकर उनकी परेशानियों को दूर कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांसद, विधायक अपने क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही, लाभान्वित व्यक्तियों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी दूर कराएं, ताकि उन्हें समय से योजना का लाभ मिल सकें। सभी सांसद और विधायकगण ग्राम स्वराज अभियान में चयनित गांवों में जाएं और चौपाल का कार्यक्रम आयोजित करें।

हर संसदीय क्षेत्र में 25 करोड़ रूपये से बनेंगी सड़के

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए से सड़क बनवाई जाएगी। सांसद स्थानीय विधायक के साथ बैठक कर ऐसी सड़कों का प्रस्ताव देंगे। सड़कों के अतिरिक्त क्षेत्र की अन्य मांगों जैसे महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, सीएचसी, ओवरब्रिज का प्रस्ताव भी देंगे। सभी सांसद और विधायक अपना कैम्प कार्यालय स्थापित करके प्रतिदिन लोगों से मिलेंगे।

वर्तमान सरकार ने बदली तस्वीर

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 8.85 लाख आवास पिछले एक वर्ष में बने हैं। इन्हें उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना में नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन, मनरेगा में 100 दिन का मानदेय, शौचालय का अतिरिक्त लाभ दिया गया है। इसके अलावा 3.60 लाख आवास शहरी क्षेत्र में बनाये गये हैं। वर्तमान सरकार के एक साल के कार्यकाल में कानून एवं व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।

हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता

प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना और हर हाल में कानून का राज स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए तहसील, थाना व ब्लाक सीधे जनता से जुड़ेंगे और सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसमस्याओं का वास्तव में पूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद कासगंज में ग्राम स्वराज अभियान, विकास कार्यो तथा कानून–व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह विचार व्यक्त किये।

वातावरण खराब करने वालों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई

अपराध पर नियंत्रण के लिए उन्होंने पुलिस को प्रभावी पेट्रोलिंग के निर्देश देते हुए कहा कि कानून–व्यवस्था का वातावरण खराब करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे सामान्यजन में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा पैदा हो। थानों में फरियादियों के बैठने, पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने जनपद में घटी आपराधिक घटना के पीड़ितों एवं गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 1090 विमेन पावर लाइन का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा और एन्टी रोमियो दलों को सक्रिय किया जायेगा।

कल्याणकारी योजनाओं का जनता को मिले लाभ

मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से गरीब, पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारी ईमानदारी से प्रयास करें। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा तथा चौराहों का सौन्दर्यीकरण होगा।

कासगंज के 10 नगर निकाय हुए ओडीएफ

कासगंज जनपद के 10 नगर निकाय पूर्णतः ओडीएफ हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 14,000 शौचालयों का निर्माण होना शेष रह गया है, जिसके उपरांत जिला पूर्णतः ओडीएफ हो जायेगा।

दैवीय आपदा पीड़ित परिवारों को सांत्वना

मुख्यमंत्री जी ने जनपद कासगंज के गांव फरौली पहुँचकर तहसील सहावर, पटियाली तथा कासगंज में दैवीय आपदा की घटनाओं में 06 मृतकों के आश्रितों तथा कस्बा सहावर व अमांपुर में डकैती की घटना के 04 मृतकों के आश्रितों एवं 08 घायलों को आर्थिक सहायता की कुल 44 लाख रुपये की धनराशि के चेक प्रदान किए।

मुख्यमंत्री जी ने डकैती तथा दैवीय आपदा की दुःखद घटना में मृतकों के परिजनों को सांत्वना प्रदान करते हुये हर संभव सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिलाया।

बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रभावी व्यवस्था

- **बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 4491 नये हैण्डपम्प का अधिष्ठापन,**
- **541 ग्रामों में टैंकर के माध्यम से की जा रही जलापूर्ति**
- **36 पाइप पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करनें हेतु हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन, पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार के कार्य कराते हुये पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

नये हैण्डपम्पों की स्थापना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 2017–18 में 2195 नये हैण्डपम्प की स्थापना तथा 2147 हैण्डपम्पों को रिबोर किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु 4815 नग हैण्डपम्प रिबोर, 1174 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य तथा पूर्व संचालित 127 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण क्षमता पर क्रियाशील करने हेतु आवश्यक कार्य पूर्ण करते हुए पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

34 लाख जनसंख्या को हो रही जलापूर्ति

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सात जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में कुल 581 पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से 1847 ग्रामों की लगभग 34 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 42 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन है, जिसके सापेक्ष 22 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, जिससे 116 ग्रामों की 245026 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है तथा पूर्व में टैंकर संचालन से प्रभावित 31 ग्रामों में टैंकर संचालन की अब आवश्यकता नही होगी। ■

दैवीय आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता

उत्तर प्रदेश में आये आंधी, तूफान, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली से 31 जिलों में जनहानि तथा पशुहानि हुई और 10 जिलों में मकान क्षतिग्रस्त हुए। दैवीय आपदा से हुई इस क्षति के सापेक्ष प्रदेश सरकार ने जनहानि के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की दर से 2 करोड़ रुपये, घायलों को 1.02 लाख रुपये तथा पशुहानि के लिए 9.18 लाख रुपये की अहैतुक सहायता राशि वितरित कर दी है। शेष का वितरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए प्रभावित परिवारों को सम्बंधित जिलों द्वारा तत्काल सहायता पहुंचाई जा रही है। आंधी, तूफान, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अब तक 1.92 लाख रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। दैवीय आपदा प्रभावित जनपदों में प्रभावित परिवारों को शत-प्रतिशत नुकसान का मानक के अनुसार राहत वितरित की जायेगी।

सीतापुर में सीएम ने जाना घायल बच्चों का हाल, दिए बेहतर इलाज के निर्देश

- मृतक आश्रितों को 2 लाख तथा घायलों को 25 हजार की मदद
- ड्रोन कैमरे लगाकर किया जा रहा है हिंसक कुत्तों का चिन्हांकन
- प्रतिदिन 24 घण्टे पुलिस द्वारा सर्च अभियान/कॉम्बिंग जारी

जनपद सीतापुर में कुत्तों के हिंसक हो जाने की घटनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गम्भीरता से संज्ञान में लेते हुए बड़े स्तर पर स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कुत्तों के हमले में घायल मासूमों व मृत बच्चों और उनके परिवारीजनों से मुलाकात कर उनका दु:ख-दर्द बांटा।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र में ड्रोन कैमरे लगाकर हिंसक कुत्तों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक करने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्र में पुलिस टीमों की काम्बिंग की व्यवस्था की गयी है। प्रशासन ने पकड़े गये 41 कुत्तों को कान्हा उपवन लखनऊ में बधियाकरण के लिए भेज दिया है।

जनपद में हिंसक हो रहे कुत्तों की घटनाओं के दृष्टिगत एक टीम प्रभावित क्षेत्र खैराबाद में कुत्ते पकड़ने का कार्य कर रही है। ये टीमें प्रात: भ्रमणशील रहकर निरन्तर ऐसे कुत्तों के चिन्हांकन का प्रयास कर रही हैं जिनके हिंसक होने की आंशका हो सकती है। पुलिस टीमों द्वारा 24 घण्टे कॉम्बिंग/सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कुत्तों का एण्टीरैबीज टीकाकरण भी किया गया है। जंगली कुत्तों की क्षेत्र में आमद की आशंका के दृष्टिगत विशेष सतर्कता के निर्देश भी दिये गये हैं।

प्रदेश में सूखा घोषित जनपदों हेतु 4899.60 लाख रुपये स्वीकृत

प्रदेश में सूखा घोषित जनपदों में सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के जीवन निर्वाह के लिए खाद्यन्न एवं अन्य राहत सामग्री वितरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 4899.60 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जनपद झांसी को 1157.37 लाख, महोबा को 697.31 लाख रुपये, मिर्जापुर को 127.90 लाख रुपये, ललितपुर को 35.28 लाख रुपये तथा सोनभद्र को 2881.80 लाख रुपये प्रथम चरण के खाद्यन्न सामग्री वितरण हेतु स्वीकृत किए गये हैं।

उत्पादों की गुणवत्ता सुधारेगी तकनीकी उन्नयन योजना

पूंजी उपादान की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये होगी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तकनीकी उन्नयन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत जनपद में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां जो उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु नयी तकनीकी मशीनें स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें मशीन कय मूल्य का 50 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा। इसकी अधिकतम सीमा 02 लाख रुपये तक रखी गई है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक उद्यमी 11 जून, 2018 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कैसरबाग, लखनऊ में सम्पर्क स्थापित कर आवेदन–पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में निवेश करेंगी अमेरिकी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश में बदलते व्यवसायिक परिदृश्य का परिणाम है कि न केवल देश वरन् विदेशों से भी प्रतिष्ठित कम्पनियां भारी मात्रा में निवेश के माध्यम से प्रदेश की विकास गाथा में सहयोगी बनने को आतुर हैं। अमेरिका की कई कम्पनियों ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बड़े निवेश की इच्छा जताई है।

बोइंग, लाकहीड, मार्टिन हनीवेल कम्पनियों ने डिफेन्स कॉरिडोर में निवेश हेतु इच्छुक है। स्टेनफर्ड विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के साथ जेई/एईएस की रोकथाम के लिए एम.ओ.यू. करेगा। जेवर एयरपोर्ट पर एम.आर.ओ. सुविधाओ को विकसित करने हेतु अनेक अमेरिकी कम्पनियों ने इच्छा व्यक्त की है। इन्टेल, औरेकल, सिस्को, थैलिस आदि बड़ी इलेक्ट्रानिक/आईटी कम्पनियां भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी। अमेजॉन द्वारा प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत उत्पाद के अमेज़न पोर्टल पर विक्रय हेतु एमओयू प्रस्तावित है। बोइंग इण्टरनेशनल कम्पनी द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित अपने फाइटर प्लेन एफ–18 के निर्माण तथा एफ–16 प्लेन के लिये सप्लाई चेन की स्थापना में रूचि दिखाई गई है। लॉकहीड मार्टिन कम्पनी ने डिफेन्स कॉरिडोर तथा जेवर एयरपोर्ट पर एमआरओ सुविधायें विकसित करने में रूचि दिखायी।

- **बोइंग, लाकहीड मार्टिन व हनीवेल डिफेन्स कॉरिडोर में निवेश की इच्छुक**
- **जेवर एयरपोर्ट पर एम.आर.ओ. हेतु अनेक कम्पनियॉ इच्छुक**
- **इन्टेल ,औरेकल, सिस्को, थैलिस आदि कम्पनियां प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी**

इसके अतिरिक्त डिफेन्स तथा एयरोनॉटिक्स, हेल्थ सेक्टर, ट्रैफिक मैनेजमेन्ट, आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स तथा इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इन्क्यूबेशन सेन्टर, आईओटी एवं साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य करने हेतु विभिन्न कम्पनियों ने अपनी रूचि प्रदर्शित की।

हाथ से मैला उठाने के अभिशाप से मिलेगी मुक्ति

40 करोड़ रुपए मैनुअल स्कैवेंजरों के खाते में स्थानांतरित

हाथ से मैला उठाने वाले के अभिशाप से लोगों को पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। इसे देखते हुए हाल ही में 40 करोड़ रुपए मैनुअल स्कैवेंजरों के खाते में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में आजतक 11225 लोग हाथ से मैला उठाने के पेशे में चिन्हित किए गए हैं। इसके सापेक्ष 9952 परिवारों को लाभान्वित कर दिया गया है। इन लोगों को स्वरोजगार के लिए अलग से एक करोड़ 58 लाख रुपए की अनुदान की राशि भी अवमुक्त की गई है। ऐसे लोगों के स्थाई रूप से पुनर्वासन के लिए इन्हें राज्य सरकार के अन्य विभागों में आउट सोर्सिंग के पदों पर समायोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना शुरू की है, जिसमें स्टैंडअप योजना के तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ की राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उद्यमिता हेतु दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हाथ से मल उठाने के कार्यों में लगे 9952 लोगों को 40 करोड़ रुपए की राशि वर्तमान केन्द्र सरकार के समय में ही दी गई है। कुछ पेशेवर जातियों की पूर्व में अनदेखी के कारण वे हाशिए पर बने रह गए हैं। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए अलग से बड़े पैकेज की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे भी विकास की धारा में शामिल होकर प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। ■

शीतगृहों के पंजीकरण एवं लाईसेंस नवीनीकरण हेतु ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना

राज्य सरकार जनसामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार ने फल पौध शाला के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को जनसामान्य तक उपलब्ध कराने हेतु ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू करने के निर्देश दिये हैं। ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से कराया जायेगा।

इस सम्बन्ध में जनहित गारण्टी सेवाओं के कार्यक्रमों को **www.janhit.uphorticulture.in** तथा **www.edistrict.up.nic.in** पोर्टल पर पंजीकृत/नवीनीकृत कराया जायेगा।

फल पौधशाला के क्षेत्रफल के अनुसार, निजी पौधशालाओं की लाईसेन्स फीस 250 रूपये से 2500 रूपये तक निर्धारित की गयी है, जबकि लाईसेन्स नवीनीकरण का शुल्क 125 रूपये से 1250 रूपये तक निर्धारित किया गया है। आवेदक को उद्यान विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु निकटतम जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई–सुविधा केन्द्र पर जाकर अनुरोध करना होगा।

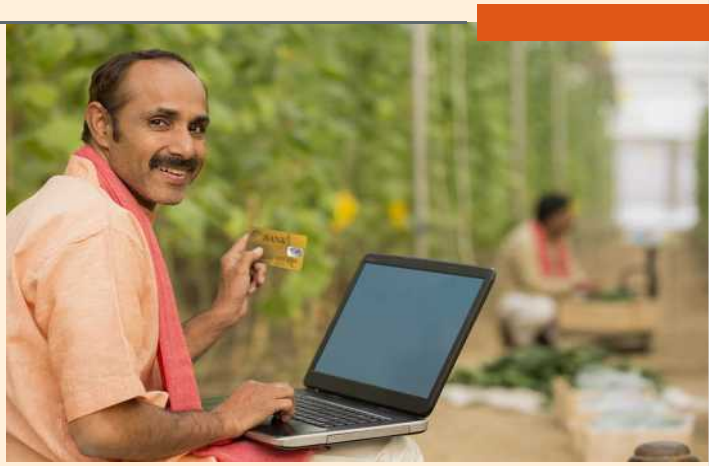

28 लाख 63 हजार किसान जुड़े एम–किसान पोर्टल से

किसानों को घर बैठे मिलेगी आधुनिक खेती संबंधी सूचनाएं और समस्याओं का होगा त्वरित निराकरण

सरकार द्वारा किसानों को घर बैठे एस.एम.एस. के माध्यम से खेती संबंधी नवीनतम आधुनिक जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु एम–किसान पोर्टल की स्थापना की गई है। प्रदेश के लगभग 33 लाख गन्ना किसानों को भी एम–किसान पोर्टल से जोड़े जाने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया, ताकि प्रदेश के गन्ना किसान भी खेती संबंधी नवीनतम जानकारियां घर बैठे एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त कर सकें और इन जानकारियों को उपयोग अपनी खेती में करके खेती की उपज और आय में वृद्धि कर सकें।

प्रथम चरण में प्रदेश के 28 लाख 63 हजार गन्ना किसानों को एम–किसान पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिसके फलस्वरूप गन्ना किसानों को घर बैठे ही खेती संबंधी आधुनिक जानकारियां एस.एम.एस से प्राप्त हो रही हैं। किसान प्राप्त जानकारियों का अधिकाधिक उपयोग कर अपनी खेती की उपज में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे, ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके।

31.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो चुकी गेहूँ खरीद

रबी विपणन वर्ष 2018–19 में समर्थन मूल्य योजना के तहत अब तक 31.17 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हो चुकी है। इस योजना से अब तक 5,61,984 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा 5,376.44 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों के खातों में सीधे कर दिया गया है। पिछले साल इस समयावधि में लगभग 17.45 लाख गेहूँ की खरीद की गयी थी। पिछले साल की तुलना में लगभग दो गुना अधिक खरीद हुई है। किसानों का गेहूँ ई–उपार्जन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से खरीदा जा रहा है, जिसका पूरा विवरण खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके साथ ही किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 18001800150 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

15 मई 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए

महत्वपूर्ण निर्णय

484 जूनियर डॉक्टर मिलेंगे 6 मेडिकल कॉलेजों को

गोरखपुर, आगरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को 484 जूनियर रेजीडेंट डॉक्टर मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस व्यवस्था पर प्रति वर्ष लगभग 36.59 करोड़ रूपये का व्यय होगा और प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार आयेगा।

गोरखपुर मेट्रो की डीपीआर बनाएगी 'राइट्स'

कृषि संबंधी लाइसेंस योजना में बढ़ा शुल्क

शीरे के अवैध व्यापार पर होगा 1 लाख का जुर्माना और एक साल की कड़ी सजा

दीनदयाल रोजगार योजना में तीन वर्ष तक ब्याज वापसी

लोकसेवा आयोग कराएगा सिविल जज परीक्षा

लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस वे पर होगा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम

लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे को 'ताज एक्सप्रेस–वे– का नाम देते हुए कैबिनेट ने इस पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

नये सिस्टम के अन्तर्गत सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी कॉलेज बॉक्स, पीटीजेड कैमरा,एएनपीआर बेस्ड स्पीड इंफोर्समेंट सिस्टम और ऑटोमैटिक काउंटर कम क्लासिफायर स्थापित किये जायेगे। एक्सप्रेस–वे पर तीन स्थानों पर कन्ट्रोल सेंटर खोले जायेंगे।

चयनित कंपनी स्थापना के साथ–साथ पांच वर्ष तक रखरखाव भी करेगी। एक्सप्रेस–वे पर यात्रियों की तत्काल सहायता हेतु मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है। ■

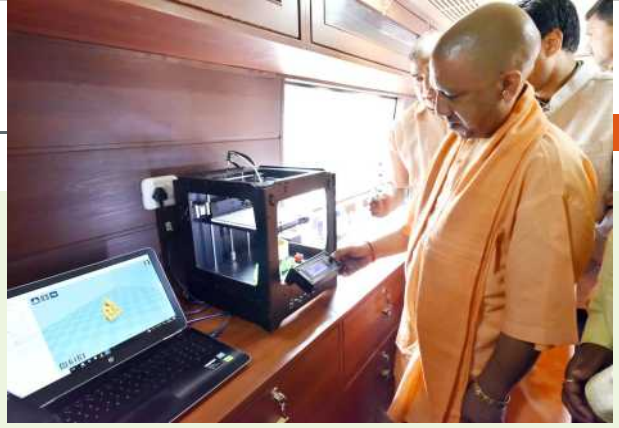

पिछड़े अंचलों में विद्यार्थियों को जागरूक करेगी विज्ञान बस

समाज के विकास में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विद्यार्थियों में विज्ञान की मौलिक समझ, इस प्रकार से विकसित की जाये जिससे कि वे अपने प्रयोगों का लाभ देश और प्रदेश को दे सकें। प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े अंचलों के विद्यार्थी भी सरल प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धान्तों को आसानी से समझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तकनीकी विशेषताओं से सुसज्जित 'विज्ञान बस' को हरी झंडी दिखाई। यह बस विभिन्न स्कूलों में 2 से 3 दिन लगातार उपलब्ध रहेगी, जिससे विद्यार्थियों को समुचित तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके। 'विज्ञान बस' के माध्यम से विज्ञान के नियमों और सिद्धान्तों को प्रयोगों के माध्यम से सुरूचिपूर्ण ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनकी समझ को विकसित किया जा सकेगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी